जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 346 प्रभात चूरू, मंगलवार 14 अप्रैल, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'सरकार को राजनीतिक दृष्टि से भी ईमानदार व तटस्थ होना चाहिए, केवल संख्या बल से सही होना पर्याप्त नहीं'

सोनिया गांधी ने अखबार में संपादकीय लेख लिखकर, चुनाव के दौरान संसद का विशेष सत्र आहूत करने के निर्णय को चुनौती दी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेज़ी दैनिक में लिखे अपने एक कड़े संपादकीय में नरेन्द्र मोदी सरकार पर महिलाओं के आरक्षण बिल को राजनीतिक लाभ में बदलने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान महिलाओं के आरक्षण बिल पर नहीं, बल्कि परिसीमन (डीलिमिटेशन) पर केन्द्रित है। सरकार इस अवसर और बिल का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को बिना जनगणना किए फिर से तय करने के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल अंकगणितीय रूप से सही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और बेदाग दिखाई देना चाहिए।

- सोनिया गांधी के लेख के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि, संसद की सीटों का परिसीमन है तथा इस परिसीमन के जरिए सरकार दक्षिण भारत की संसदीय सीटों की संख्या कम करना है।
- इस परिसीमन से दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व घट जाता है तथा कांग्रेस पार्टी को दक्षिण भारत की पार्टियों को बगावत के झंडे के नीचे एकत्रित करना है, और उनको यह समझाया जा रहा है, अगर वे एक झंडे के नीचे नहीं हुए तो राजनीति की दृष्टि से व प्रशासन की दृष्टि से अप्रसांगिक हो जाएंगे।

परिसीमन के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल चुनावी लाभ लेने और चुनाव जीतने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उनका एकमात्र उद्देश्य और प्राथमिकता यही है।

चुनाव के बीच विशेष सत्र की आवश्यकता के खिलाफ बोलते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने सही और गलत का ध्यान रखना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका एकमात्र ध्यान चुनाव जीतने पर है, और चुनाव आयोग सरकार के साथ पूरी तरह गठबंधन में है।

जनगणना और परिसीमन पर सरकार की यू-टर्न नीति स्पष्ट और उल्लेखनीय है, जो एक ऐसी सरकार के बारे में बहुत कुछ बता रही है, जिसका ध्यान केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ पर केन्द्रित है।

महिलाओं का आरक्षण बिल, जिसे 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो परिसीमन है।

कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए तीन दिवसीय सत्र में उपस्थित रहने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकन चीता बारां के जंगलों में पहुँचा

छबड़ा, 13 अप्रेल (निसं)। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के बारां जिले के जंगलों में पहुंचा अफ्रीकन चीता "केपी-3" इन दिनों लगातार मूवमेंट कर रहा है। सोमवार को यह चीता छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में पहुंच गया। इस

- वन विभाग छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में चीता "केपी-3" के मूवमैंट पर लगातार नज़र रख रहा है।

दौरान वन विभाग टीम ने लगातार उसके मूवमेंट पर नज़र बनाए रखी।

यह चीता पार्वती नदी किनारे होते हुए यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसे पेड़ों की छांव में आराम करते देखा गया और उसने आसपास के क्षेत्र में हल्की चहलकदमी भी की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ के अनुसार, चीते की मौजूदगी की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हो गई थी, जिसके चलते लोग उसे देखने के लिए उत्सुक नजर आए। पूरे दिन चीते की गतिविधियां संबंधित क्षेत्र में ही सीमित रहीं।

वन विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि चीते की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। यहां छबड़ा रेंज के साथ -साथ एमपी के वनकर्मी भी मौजूद हैं। निगरानी के दौरान छबड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने जहाजों को चेतावनी देनी शुरु की कि ब्लॉकेड शुरु हो गया है

पर चेतावनी से एक बात साफ हुई की अगर कोई भी जहाज ईरानी "ऑयल" ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे बमबारी से उड़ा दिया जाएगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। डॉनल्ड ट्रम्प की होर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी की धमकी सोमवार शाम से शुरू हो गई है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इस बीच, ट्रम्प ने ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खोल लिया है। इस बार, ट्रम्प ने पोप लियो चौदहवें के साथ विवाद खड़ा किया। पोप ने पहले ट्रम्प के ईरान युद्ध की आलोचना की थी। ट्रम्प ने खुद को एक शांत तस्वीर में ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत किया, और इस कदम ने लाखों ईसाइयों को नाराज़ कर दिया।

कुछ समय से, ट्रम्प ने पोप पर तीखे हमले किए हैं, यह कहते हुए कि वह विदेशी नीति या अपराधों के मामलों पर बोलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। पोप का अपमान करना ट्रम्प के लिए कूटनीतिक मुसीबत और रणनीतिक गलती साबित हो सकता है, क्योंकि होर्मुज़ नाकेबंदी की शुरुआत के साथ उन्होंने अपने

- पर, सवाल यह उठ रहा है कि ये जहाज अगर रूस और चीन जा रहे होंगे तो भी क्या अमेरिका उन्हें उड़ा देगा।
- अमेरिका का यह "ब्लॉकेड" ईरान के लिए गंभीर धमकी है। क्योंकि, युद्ध के दौरान भी ईरान अपना "ऑयल" बेचकर काफी राजस्व प्राप्त कर रहा था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसे-जैसे ऑयल के दाम बढ़ने लगे। ईरान की आमदनी भी वैसे-वैसे बढ़ती जा रही थी।
- अब यह आमदनी अगर बंद हो गई तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अतः ईरान ने पुतिन से बात की है, हस्तक्षेप करने के लिए।

आक्रमण को पूरी तरह से एक नए क्षेत्र में फैला दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नाकेबंदी का कदम खतरों और अज्ञात जोखिमों से भरा है। किन्हीं भी क्रूड तेल ले जाने वाले जहाजों या उर्वरक से लदे जहाजों की नाकेबंदी, जिनकी भारी मांग है, आगे और भी टकराव को जन्म दे सकती है। पहले से ही जटिल संघर्ष और बिगड़ सकता है और अन्य देश इसमें फंस सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही जहाजों को नाकेबंदी के बारे में संकेत दे चुका है। लेकिन सोचिए, अगर नाकेबंदी में चीन या रूस को क्रूड भेजने वाले जहाज शामिल हों, तो क्या अमेरिका उनकी यात्रा रोक सकता है? और यदि अमेरिका ने इन जहाजों को भी रोका, तो रूस या चीन की प्रतिक्रिया क्या होती?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने अरूणाचल में "नामकरण" अभियान शुरु किया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम की आलोचना की और दोनों देशों के संबंधों में नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। जब भारत सरकार खाड़ी संकट के संभावित और नकारात्मक आर्थिक प्रभावों में व्यस्त है, पूर्वी सीमाओं पर संकट बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जिलों, गांवों, पहाड़ों और नदियों के नाम बदलने के अभियान को फिर से जारी कर दिया है।

2025 के अंत तक, चीन ने अरुणाचल में 89 स्थानों के नाम बदलने के पांच बैच जारी किए हैं। यह प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई और 2021, 2023, 2024 और 2025 में जारी रही। चीन अरुणाचल को ज़ांगनान या दक्षिण तिब्बत कहता है और अरुणाचल के लगभग 83,000 से 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर अपना क्षेत्रीय अधिकार जताता है। इसने 1914 के

- पूरा विश्व ईरान वॉर की समस्याओं से त्रस्ट है, खासकर भारत का पूरा ध्यान पैट्रोल व एलपीजी संकट से निपटने पर है, ऐसे में चीन ने अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नया नाम रखना शुरु कर दिया है।
- चीन ने यह कार्यवाही 2017 में शुरु की थी तथा 2017 से 2025 तक नए नामों के 5 बैच जारी कर चुका है।
- चीन में अरूणाचल को जांगनान या दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। चीन ने 1914 में शिमला समझौते के तहत बनी मैकमोहन रेखा को पहले ही ठुकरा दिया है और वह अरूणाचल पर दावा जताता रहा है।

शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच स्थापित मैकमोहन रेखा को खारिज कर दिया है। चीन पश्चिमी लद्दाख में अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी अपने क्षेत्रीय अधिकार का दावा करता है।

चीन की इस गतिविधि पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन नैरेटिव कथाओं का निर्माण करने और झूठे दावे पेश करने का "शरारती प्रयास" बताया। विदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी किया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वे आगामी 16 से 18 अप्रैल तक होने वाली सदन की तीन दिवसीय विशेष बैठक में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें।

कांग्रेस ने आधिकारिक बयान में कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक

- महिला आरक्षण अधिनियम एवं परिसीमन में जुड़े विधेयकों व संशोधनों को पेश करने के आयोजित किया जा रहा है विशेष सत्र।

लोकसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और मतदान होना है, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है।

पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए यह व्हिप उस वक्त जारी किया है, जब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेल, एलपीजी के बाद अब सल्फर आपूर्ति भी खतरे में

ईरान जंग का दुष्परिणाम सल्फर आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जो कि खाद, बैटरी, सेमीकंडक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। जब घर-घर ईंधन की कीमतों और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता है, तब ईरान युद्ध के बीच, एक और धीमा, लेकिन गंभीर व्यवधान पृष्ठभूमि में उभर रहा है। यह व्यवधान सल्फर से जुड़ा है, जो उर्वरक, बैटरी, रसायन, धातु और यहां तक कि सेमीकंडक्टर के लिए एक आवश्यक मूल तत्व है।

यूरिया से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक, सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन लाइनों के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास यह व्यवधान आपूर्ति में झटका पैदा कर रहा है, जो कारखानों के उत्पादन को धीमा कर सकता है और खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है।

मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र में भेजी जाने वाली सल्फर का आधा भाग होर्मुज़

- सल्फर की आपूर्ति बाधित हुई तो भारत में सरकार पर खाद सब्सिडी का अतिरिक्त भार पड़ेगा, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलेगी, खाद्यान्न महँगा हो जाएगा और रसायन व धातू निर्माण संयंत्रों की लागत भी बढ़ जाएगी।
- मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार, विश्व भर में सल्फर की कुल आपूर्ति का 50 प्रतिशत होर्मुज़ से गुजरता है और 28 फरवरी के बाद से 44,000 कंपनियों के "शिपमैंट" अवरुद्ध हो चुके हैं।

स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इन हैण्ड ब्रैड स्ट्रीट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, वॉर शुरु होने के बाद से 44,000 कंपनियों का एक एक शिप कैंट प्रभावित हुआ है।

सल्फर मुख्य रूप से तेल और गैस परिष्करण का बाय प्रॉडक्ट है। वैश्विक निर्यात का 45 प्रतिशत से अधिक खाड़ी देशों के पास है। मूल रूप से, किसी भी तेल व्यवधान का असर जल्दी ही सल्फर आपूर्ति पर पड़ता है।

दुनिया भर की सल्फर की कुल मांग का लगभग 60 प्रतिशत उर्वरकों से आती है। बाकी का इस्तेमाल रसायन, धातु प्रसंस्करण, बैटरी और चिप निर्माण में होता है।

भारत अपनी सल्फर आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है, मुख्यत: यूरिया और फॉस्फेट उर्वरकों के लिए। किसी भी लंबी अवधि का व्यवधान भारी प्रभाव दिखा सकता है, जैसे सरकार के लिए उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ना, किसानों के लिए उच्च इनपुट लागत, आपूर्ति सघन होने पर खाद्य महंगाई का खतरा, रसायन और धातु उत्पादकों के लिए लागत में वृद्धि।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया, जो कि प्रमुख निकल उत्पादक है, अपनी सल्फर का लगभग 75 प्रतिशत मध्य पूर्व से आयात करता है। भारत भी उर्वरक से जुड़ी मांग के लिए इसी तरह की निर्भरता में बैठा है। इसलिए, ईरान संघर्ष लंबा चलता है तो यह दबाव बना रहता है। वास्तव में, द सौफान सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए हालिया शोध और विश्लेषण में निष्कर्ष निकला है कि उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान जल्दी ही खाद्य सुरक्षा जोखिम में बदल सकता है।

बंगाल में एक्शन मोड़ में है ईडी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रेल। एन्फोर्समेन्ट डायरैक्वरेंट (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने कई घोटालों से जुड़े उच्च प्रोफ़ाइल छापों और संपत्ति जब्तियों की श्रृंखला शुरू की है, जिनमें भर्ती घोटाला, जमीन

- राज्य में ईडी ने कई घोटालों की लिस्ट बनाई है और उसके आधार पर तृणमूल नेताओं व सरकार के अफसरों पर धड़ाधड़ रेड कर रही है।

हड़पना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गेहूं का गबन शामिल है।

मार्च के अंत और अप्रैल 2026 की शुरुआत में हुई गतिविधियों की तूफ़ानी श्रृंखला में, केन्द्रीय एजेंसी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर जीत का मार्जिन, काटे गए वोटर्स की संख्या से कम है तो हम हस्तक्षेप करेंगे'

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर के संबंध में दायर याचिकाओं के बारे में हो रही सुनवाई के दौरान बहुआयामी टिप्पणी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने केवल पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर के दौरान संदिग्ध मतदाताओं की "तार्किक असंगति" सूची बनाई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने यह टिप्पणी की और कहा कि अब पश्चिम बंगाल में मतदाता विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंस गए हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने यह टिप्पणी उस समय की, जब चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आयोग के नोटिसों का निर्णय करने वाले न्यायिक अधिकारियों के कुल मामलों का 47 प्रतिशत खारिज किया गया।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "यह अंतिम साधन को न्यायसंगत बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि साधन अंत को न्यायसंगत बनाने के लिए हैं। यह राज्य और चुनाव आयोग के बीच कोई संघर्ष नहीं है। यह आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी नहीं है। यह तो मतदाता के दो पाटों के बीच फंसने का मामला है। अदालतों ने केवल चुनाव को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, रोकने के लिए नहीं।"

लेकिन न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि जब तक "अत्यधिक संख्या में मतदाता (मतदान से) बहिष्कृत नहीं होते," चुनाव के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "यदि 10 प्रतिशत मतदाता वोट नहीं करते और जीत का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक है, तो... यदि यह 5 प्रतिशत से कम है तो हमें विचार करना होगा। पहले किसी

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि बंगाल में वोटर, संसदीय अथॉरिटीज चुनाव आयोग व राज्य सरकार के बीच में पिस रहा है। अतः सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत के अनुरुप काम कर रहा है कि चुनाव कराने को प्रोत्साहित करना चाहिए, चुनाव रद्द करने को नहीं।
- अतः, अगर 10 प्रतिशत वोटर, वोट नहीं कर पाए तथा उदाहरण के लिए जीत का मार्ज़िन कम, पाँच प्रतिशत, है तो हम हस्तक्षेप करेंगे।

उम्मीदवार को अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि किसी उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। कृपया यह न सोचें कि हम यह नहीं सोच रहे कि बहिष्कृत मतदाताओं का क्या होगा।"

न्यायमूर्ति बागची ने पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर के बीच भिन्नताओं पर भी प्रकाश डाला, विशेषकर तार्किक असंगति सूची के निर्माण में।

उन्होंने कहा, "हमने संवैधानिक प्राधिकरण को मतदाता सूची की शुद्धता के मुद्दे में जाने की अनुमति दी है। आपके एसआईआर पर आपकी मूल ईसीआई अधिसूचना ने 2002 की सूची को नहीं छुआ। लेकिन आपकी तार्किक असंगति सूची अस्वीकरण का कारण 2002 की सूची आदि हैं। आपकी अधिसूचना उन लोगों को प्रभावित करती है, जो 2002 की सूची से संबंधित हैं, अर्थात 2002 की सूची मानक है। अंतिम सूची में आपने 2002 की सूची के सदस्यों को नहीं हटाया। जब बिहार एसआईआर पर विचार हुआ, तो आयोग की प्रस्तुतियाँ स्पष्ट थीं कि 2002 की सूची के सदस्यों को कोई दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बिहार के मामले में अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ देखें। आपने कहा था कि 2002 के मतदाता को दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है।"

जब चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील डी.एस. नायडू ने कहा कि लोगों को यह साबित करना होगा कि वे 2002 की सूची वाले ही व्यक्ति हैं, न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "अब आप पहले की प्रस्तुतियों में सुधार कर रहे हैं।"

न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय प्रक्रिया के दौरान कुछ त्रुटियां की होंगी।

उन्होंने कहा, "यदि आप दिन में 1000 दस्तावेज़ देखते हैं, और सटीकता 70 प्रतिशत है, तो इस गतिविधि को उत्कृष्ट माना जाना चाहिए। इसलिए त्रुटि की संभावना होगी और हमें एक मजबूत अपीलीय मंच की आवश्यकता है।"

मतदान के अधिकार को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तृणमूल अलगाववादियों का समर्थन करती है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अप्रेल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते

- प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी में एक सभा में कहा, चिकन्स नैक को काट कर उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की धमकी देने वाली टुकड़े-टुकड़े गैंग का तृणमूल समर्थन करती है।

हुए कहा कि सिलीगुड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य की सत्ताधारी पार्टी को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)